

सेवा के लिए नियुक्ति। इसलिए, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों को खारिज करने में हमारे पास कोई संकोच नहीं है।

(17) परिणाम में 1999 के CWP 11874 को खारिज कर दिया जाता है, जबकि CWPS 6982, 2000 के 6354 और 2001 के 1113 को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और आयोग को उन सभी नामित उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिनके सेवा रिकॉर्ड को भेजा गया था और इसकी सिफारिश की गई थी। राज्य सरकार ऐसे सभी व्यक्तियों का नाम है, जो कानून के अनुसार नियुक्तियां करने के लिए सरकार के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

आर.एन.आर.

जवाहर लाल गुप्ता और आशुतोष मोहन्टा से पहले, जेजे

एम/एस मोंगा राइस मिल्स, -पुटिशनर

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य उत्तरदाता

सी -डब्ल्यू.पी. 2000 का नंबर 8532

28 अगस्त, 2001

भारत का संविधान, 1950-आर्ट्स। 226 और 286-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1996 का अधिनियम संख्या 33) -SS। 5 और 15 (सीए) -हियाना जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1973-S.12- निर्देश दिनांक 29 नवंबर, 2000 को हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया था-एक एक्सपोर्टर को चावल की बिक्री के लिए एक मिलर द्वारा खरीदे गए धान पर खरीद कर की खरीद कर। धान और चावल-डिस्टिंक्शन बीच-अलग-अलग वस्तुओं-सीएल। (सीए) 1956 के एस। 15 के एस। एसीटी ने चावल और धान को केवल एस 5 (3) -s द्वारा कवर किए गए लेनदेन के संबंध में एक एकल वस्तु के रूप में माना। 5 (1) एक विदेशी खरीदार को एक निर्यातक द्वारा चावल की बिक्री पर कर की लेवी को छूट देता है और एक मिलर से एक निर्यातक द्वारा चावल की खरीद पर छूट देता है। धारा 5 (3) के तहत कवर किए गए एक विदेशी खरीदार को सीधे चावल की बिक्री, जबकि 1956 अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत या धारा 12 के तहत या तो चावल की बिक्री के लिए

चावल की बिक्री के लिए एक मिलर द्वारा धान की खरीद का लेन -देन। 1973 अधिनियम-याचिकाकर्ता ने धान की खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया- राज्य सरकार ने अधिकारियों के एक निर्णय के लिए ध्यान आकर्षित करने वाले निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने अधिकारियों को कला के तहत अधिकार क्षेत्र के ऐसे प्रशासनिक निर्देशों को जारी करने में कानूनी दुर्बलता नहीं। **226** अपील के उपाय को समाप्त किए बिना, रिट याचिका की स्थिरता के लिए बार-बार बार, कोई भी, कोई भी, तथ्यों और लेनदेन में जांच से जुड़े मामलों को कला के तहत कार्यवाही में निपटा नहीं जा सकता है। **226**-रिट ने खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ, यदि कोई हो, तो अपील दायर करने की अनुमति दी। आयोजित, कि सेंट्रल की धारा **14 (i) (i और ii)** का एक अवलोकन बिक्री कर अधिनियम, **1956** स्पष्ट रूप से दिखाता है कि धान और चावल दो अलग -अलग वस्तुएं हैं। सीएल का परिचय देकर (सीए) धारा १५ की, धारा ५ के उप-धारा (३) के प्रयोजनों के लिए काल्पनिक रूप से विस्थापित किया गया है। इस प्रावधान ने पूरी तरह से भेद नहीं किया है। इसने एक सीमित उद्देश्य के लिए चावल और धान को एक वस्तु के रूप में माना है। इस संशोधन से, इसने मिलर को सक्षम किया है जो धान की खरीद पर कर के करार से बचने के लिए प्रत्यक्ष निर्यातक हैं। हालांकि, यह लाभ उन मिलर्स को उपलब्ध नहीं कराया गया है जो एक निर्यातक को बेचते हैं और सीधे निर्यात नहीं करते हैं। संसद लोगों के हितों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। यह अनुभव द्वारा प्रकट की गई जरूरतों के आधार पर मूर्तियों को लागू करता है। सीमित कल्पना को पेश करने वाला प्रावधान संवैधानिक मापदंडों के भीतर है। यह एक उचित संतुलन पर हमला करता है। हम इस कल्पना को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं कि स्थिति के व्यक्त शब्द क्या प्रदान करते हैं।

(पैरा २० और ३५)

आगे आयोजित, कि निर्यातक द्वारा बिक्री और खरीद को छूट दी जाती है। निर्यातक द्वारा बिक्री को खंड (1) में प्रावधान के आधार पर छूट दी गई है और खरीद को केंद्रीय अधिनियम की धारा 5 के खंड (3) के तहत कवर किया गया है। निर्यातक द्वारा चावल की खरीद से पहले किसी भी लेन -देन को माल के निर्यात के दौरान बिक्री या खरीद के रूप में नहीं माना जाता है। इस प्रकार, यह कानून के तहत कर के लेवे से छूट के प्रावधान द्वारा कवर नहीं किया गया है।

(पैरा ३६)

इसके अलावा, कि एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत एक याचिका की रखरखाव के लिए एक पूर्ण बार नहीं है। यह भी सही है कि जब किसी कानून के वायरस शामिल होते हैं या संवैधानिक महत्व का मुद्दा उठता है,

नागरिक आम तौर पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का हकदार हो सकता है। हालांकि, तथ्यों को शामिल करते हुए और लेनदेन की जांच में, रिट कोर्ट में एक स्पष्ट बाधा है। आम तौर पर, यह सबूत रिकॉर्ड नहीं कर सकता है और तथ्य के सवालों पर निष्कर्ष नहीं दे सकता है। इन्हें स्थिति के तहत अधिकारियों द्वारा हमेशा निर्धारित किया जाना चाहिए। यह केवल तब होता है जब एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त होता है या एक वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में होता है जो अदालत सर्टिफिकेट के एक रिट के मुद्दे से हस्तक्षेप करती है।

(पैरा 38)

इसके अलावा, कि एक वैधानिक प्राधिकारी में कानून द्वारा निहित विवेक को प्रशासनिक निर्देशों के मुद्दे से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, अधिकारियों का ध्यान केवल क्षेत्राधिकार न्यायालय के निर्णय के लिए आमंत्रित किया गया है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल अधिकारियों के नोटिस के लिए निर्णय लाने से, राज्य सरकार ने अपने विवेक को नियंत्रित, नियंत्रित या सीमित कर दिया है।

(पैरा ४२)

मंचित सरिन, वरिष्ठ अधिवक्ता एम/एस के साथ। बेशर्म याचिकाकर्ता के लिए झिंगन और अवनेश झिंगन, अधिवक्ता।

सूर्य कांत, अधिवक्ता जनरल, हरियाणा के साथ पलिका मोंगा, एएजी, हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

प्रलय

जवाहर लाल गुप्ता, जे

(1) क्या धान एक मिलर द्वारा खरीदा गया है जो चावल को निर्यातक को बेचता है जो खरीद टेक्स की लेवी के लिए योग्य नहीं है? यह प्राथमिक प्रश्न है जो 53 रिट याचिकाओं के इस समूह में विचार के लिए उत्पन्न होता है। 1999 के CWP नंबर 4379 इस मुद्दे को शामिल करते हुए इस अदालत की एक बेंच द्वारा भर्ती कराया गया था। यह इस बेंच के दैनिक बोर्ड पर था। शेष 52 याचिकाएं 31 जुलाई, 2001 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं। पार्टियों के वकील ने एक अनुरोध किया कि

सभी याचिकाओं को एक साथ सुना और निपटाया जाए। नतीजतन, हमने इन पेटिशन को सुना है। पार्टियों के लिए सीखा वकील ने 2000 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8532 में तथ्यों का उल्लेख किया है। इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(२) याचिकाकर्ता के पास एक शेलर है। यह धान खरीदता है, इसे संसाधित करता है और चावल बेचता है। इसमें, हम एक निर्यातक को चावल की बिक्री से चिंतित हैं, जिसने इसे एक विदेशी खरीदार को बेच दिया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि संविधान के अनुच्छेद 286 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 और 15 (सीए) के प्रावधानों के मद्देनजर (इसके बाद 1956 अधिनियम के रूप में संदर्भित), राज्य धान पर खरीद कर नहीं लगा सकता है निर्यातक को चावल की बिक्री के लिए इसे खरीदा गया।

(३) याचिकाकर्ता ने चार मूल्यांकन वर्षों के लिए बिक्री कर रिटर्न दायर किया। 1996-97 से 1999-2000 हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1973 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार (इसके बाद 1973 अधिनियम के रूप में संदर्भित)। इसने उस कर को जमा किया जो रिटर्न के अनुसार गिर गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि धान पर कोई भी खरीद कर नहीं था, जिसे विदेशी खरीदार को निर्यातक द्वारा चावल की बिक्री के अनुबंध को पूरा करने के लिए शेल किया गया था। यह दावा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15 (सीए) और धारा 5 के प्रावधानों के आधार पर किया गया था।

(४) १६ अगस्त १९९९ को, सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल ने सिरसा विज़ के एक डीलर द्वारा किए गए एक समान दावे को स्वीकार किया। बिक्री कर अपील संख्या 698 के 1998-99 के मैस में एम/एस वीरुमल मोंगा एंड संस। हालांकि, हरियाणा राज्य ने हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 41 के तहत एक समीक्षा याचिका दायर की और दावा किया कि यह आदेश कानून के प्रावधानों के विपरीत था। राज्य की दलील को स्वीकार कर लिया गया। 15 मई, 2000 को वीड ऑर्डर, ट्रिब्यूनल ने कहा कि निर्धारिती धान पर खरीद कर के भुगतान से छूट का हकदार नहीं था।

(५) ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, आकलन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि कर, ब्याज और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता है। नोटिस की प्रतियां याचिका के साथ p.3 से P.6 से अनुलग्नक हैं।

(६) याचिकाकर्ता मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। इसने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर आवश्यक रूपों का उत्पादन किया कि चावल को वास्तव में भारत से बाहर निर्यात करने वाले द्वारा निर्यात किया गया था, जिनके

पास विदेशी खरीदार से एक पूर्व आदेश था। इसने दावा किया कि कोई भी टैक्स लेबल नहीं था। इस प्रकार, ब्याज चार्ज करने या जुर्माना लगाने का सवाल नहीं उठना था।

(7) जबकि यह मामला मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष लंबित था, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत से संपर्क किया। इस अदालत की एक पीठ ने नोटिस ऑफ मोशन के मुद्दे को निर्देशित किया। उत्तरदाताओं ने एक लिखित बयान दायर किया। उत्तर के साथ, मूल्यांकन आदेशों की प्रतियों को सामूहिक रूप से अनुलग्नक R.1 के रूप में उत्पादित किया गया था। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन किया ताकि न केवल अनुलग्नक P.3 से P.6 पर नोटिसों को चुनौती दी जा सके, बल्कि मूल्यांकन के आदेश भी, जिनमें से प्रतियों को अनुलग्नक P.11 से P.14 के रूप में उत्पादित किया गया है।

(8) याचिकाकर्ता का कहना है कि पैडी की खरीद के इलाज में उत्तरदाताओं की कार्रवाई कर की लेवी के रूप में योग्य है, 1956 अधिनियम की धारा ५ और १५ (सीए) के प्रावधानों के विपरीत है। यह प्रार्थना करता है कि नोटिस के साथ -साथ मूल्यांकन के आदेशों को भी समाप्त कर दिया जाए।

(9) उत्तरदाताओं ने लिखित बयान पर निर्भरता रखी मूल अप्रकाशित याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया। इस लिखित बयान में, यह अंतर है कि याचिकाकर्ता एक पंजीकृत डीलर है। यह खरीद में लगे हुए हैं, धान की तड़पते हैं और चावल की बिक्री करते हैं। चूंकि खरीद कर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए गए थे "राज्य अधिनियम की धारा 28-बी के तहत अनंतिम मूल्यांकन के माध्यम से खरीद कर की लेवी के लिए। याचिकाकर्ता अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ। नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करके। याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिसों के संबंध में मूल्यांकन आदेशों को योग्यता पर पारित किया गया था, (अनुलग्नक आर। 1 के रूप में संलग्न आदेश की प्रतियां)। याचिकाकर्ता के पास उस आदेश से अपील का अधिकार है। इसने संपर्क किया है। अपील के उपाय को समाप्त किए बिना माननीय कोर्ट ... "इस आधार पर, यह बनाए रखा जाता है कि रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।

(१०) योग्यता पर, यह बताया गया है कि मामले की परिस्थितियों में धान की खरीद कर की लेवी के लिए विशिष्ट है। धारा 15 (सीए) का प्रभाव केवल "यूनाइटेड रिकलैंड लिमिटेड में इस माननीय अदालत के फैसले के प्रभाव को

बढ़ाने के लिए है और एक अन्य वी। हरियाणा और अन्य (1) के रूप में ज्यादा से ज्यादा धान की खरीद धारा 5 (3) के कानूनी कथा साहित्य के आधार पर राइस मिलर-सह-निर्देशक निर्यातक केंद्रीय अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत निर्यात के दौरान खरीद बन गया। लेकिन यह कानूनी कथा वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए आगे नहीं बढ़ती है। अपने बाजार से खुद का अधिकार में धान को खरीदा और मिल्ड "इट। याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष निर्यातक को चावल की बिक्री भारत से बाहर निर्यात के दौरान बिक्री है। धारा 5 (3) याचिकाकर्ता द्वारा धान की खरीद की रक्षा नहीं करता है। इस प्रकार, दावा के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित किया गया है। यह आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि इसका प्रतिनिधि 26 जून, 2000 को आकलन प्राधिकरण के सामने आया था या उसने 'एच' फॉर्म या एस। टी। 15-ए फॉर्म को जगह देने की अनुमति मांगी थी। रिकॉर्ड पर गलत है।

(११) उत्तरदाताओं का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत इस न्यायालय के अतिरिक्त-सामान्य अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कोई मामला नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मैदानों को विरोधाभास किया गया है। यह प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका को लागतों के साथ खारिज कर दिया जाए।

(१२) श्री एम.एल. सरीन, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील सीखा कि राज्य ने निर्यात के दौरान खरीदे या बेचे जाने वाले सामानों की बिक्री या खरीद पर कर लगा नहीं दिया। धान और चावल और विशेष सामान। धान और चावल के बीच का अंतर संसद द्वारा धारा 15 (सीए) द्वारा इंट्रोड्यूसिंग करके विच्छेदित किया गया था, राज्य धान की खरीद पर लेवी और कर के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि चावल को उस निर्यातक को बेच दिया गया था, जिसके पास खरीद का पूर्व आदेश था एक विदेशी खरीदार से। उन्होंने आगे कहा कि चावल और धान के बीच के अंतर को जिस कानूनी कथाओं से हटा दिया गया है, उसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना है और इस प्रकार, लागू किए गए नोटिस के साथ -साथ मूल्यांकन के आदेशों को भी बनाए नहीं रखा जा सकता है। यह आगे कहा गया था कि याचिकाओं में उठाए गए संवैधानिक मुद्दों के मद्देनजर, अपील का उपाय रिट याचिका की स्थिरता के लिए एक बार के रूप में काम नहीं कर सकता है। सीखा वकील के अनुसार, यहां तक कि अनंतिम मूल्यांकन के आदेश पूरी तरह से मनमाना थे क्योंकि यह मामला लंबे समय तक मूल्यांकन प्राधिकरण के साथ लंबित था।

(१३) याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे को श्री सूर्य कांत, अधिवक्ता, जनरल, हरियाणा द्वारा विरोधाभास किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों की कार्रवाई कानून के साथ सख्त अनुरूप थी। केंद्रीय अधिनियम में संशोधन केवल मिलर को लाभान्वित करने के

644I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2002 (1)

लिए था, जिसने सीधे एक विदेशी खरीदार को माल निर्यात किया था। यह उन मिलर्स को कोई लाभ नहीं देता है जिन्होंने धान को खरीदा था और निर्यातक को चावल बेचा था। अनंतिम मूल्यांकन के आदेशों के संबंध में, वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के पास अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपचार प्रभावी है।

रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए कोई आधार नहीं है।

(१४) पार्टियों के लिए वकील सुनने के बाद, हम पाते हैं कि इस अदालत के विचार के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

- (i) क्या याचिकाकर्ता द्वारा खरीद कर की लेवी के लिए धान की खरीद है?
- (ii) क्या याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के तहत उपचार के लिए फिर से आरोपित किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन के आदेशों की चुनौती का संबंध है?

Reg: (i)

(१५) माल की बिक्री इंटर-स्टेट या अंतर-राज्य हो सकती है। जब अनुच्छेद 269 (1) (जी) के प्रावधानों के आधार पर अंतर-राज्य व्यापार के दौरान बिक्री या खरीद होती है, तो कर को भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जा सकता है। हालांकि, इसे "वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को सौंपा जाना चाहिए जैसा कि कानून द्वारा संसद द्वारा तैयार किया जा सकता है"। अनुच्छेद 286 के तहत, राज्य की शक्ति पर कुछ सीमाओं को बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए रखा गया है, जो "भारत से बाहर आयात या निर्यात के दौरान" होती है। संसद के पास यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार करने की शक्ति है कि जब माल की बिक्री या खरीदारी की खरीदारी या खरीद के किसी भी तरीके से अनुच्छेद 286 (1) में उल्लिखित कानून की खरीद होती है। अभी भी, सूची-II में प्रवेश 54 के आधार पर, राज्य में "समाचार पत्रों के अलावा अन्य सामानों की बिक्री या खरीद" पर कर लगाने की शक्ति है। यह शक्ति सूची-I में 92A में प्रवेश के अधीन है जो संसद को "आयात और निर्यात पर करों" को ले जाने के लिए सशक्त बनाती है। स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य द्वारा लगाया गया कर विदेशी के साथ-साथ अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं। अनुच्छेद 286 (3) के तहत, कानून ने राज्य द्वारा अब तक के लिए प्रावधान किया है, क्योंकि यह अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर की लेवी के लिए प्रदान करता है। ... दरों के लेवी और कर की अन्य घटनाओं के आकलन के संबंध में इस तरह के प्रतिबंधों और

शर्तों के अधीन होना चाहिए क्योंकि संसद द्वारा कानून निर्दिष्ट किया जा सकता है "। इस प्रकार, अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के साथ-साथ विशेष महत्व के सामानों के आयात और विस्तार से संबंधित मामलों में, संविधान संसद के वर्चस्व को मान्यता देता है जहां तक बिक्री कर आदि को लागू करने का संबंध है।

(१६) संविधान के तहत और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में सत्ता के अभ्यास में, संसद ने १९५६ अधिनियम बनाया है। बुनियादी वस्तुओं में से एक राज्य सरकारों को अंतर-राज्य व्यापार के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर कर एकत्र करने और कर एकत्र करने के लिए अधिकृत करना था। इसका उद्देश्य माल की बिक्री या खरीद के सीट्स को ठीक करना भी था। (17) १९५६ अधिनियम के प्रावधानों को १९५५ (और १९५५ के वर्षों के दौरान लागू किया गया था। अध्याय- I में मुख्य रूप से प्रारंभिक प्रकृति के प्रावधान शामिल हैं। यह कानून में उपयोग किए गए विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है। अध्याय- II सिद्धांतों का प्रतीक है "यह निर्धारित करने के लिए कि वस्तुओं की बिक्री या खरीद अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य या किसी राज्य के बाहर या आयात या निर्यात के दौरान" के दौरान होती है "। अध्याय- III अंतर-राज्य बिक्री कर की लेवी से संबंधित है। आयात या निर्यात के दौरान माल की बिक्री या खरीद के बारे में प्रावधान धारा 5 में निहित है। इस प्रावधान का एक संदर्भ उचित चरण में किया जाएगा। अध्याय- IV विशेष महत्व के सामानों से संबंधित है। धान और चावल को अलग-अलग वस्तुओं के रूप में उल्लेख किया गया है। धारा 15 किसी राज्य के भीतर घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर के संबंध में प्रतिबंधों और शर्तों से संबंधित है। यह संविधान के अनुच्छेद 286 (3) (ए) के प्रावधान के लिए संदर्भित है। 1996 के अधिनियम 33 द्वारा, क्लॉज (सीए) को प्रावधान में जोड़ा गया था। इस प्रकार, प्रासंगिक प्रावधान के तहत पढ़ता है:-

"जहां धारा 14 की उप-खंड (i) में संदर्भित धान की बिक्री या खरीद पर एक कर कानून के तहत लेविबल है और ऐसे धान से खरीदे गए चावल को भारत से बाहर निर्यात किया जाता है, फिर, उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, उप-धारा के प्रयोजनों के लिए (३) धारा ५ में से, धान और चावल को एकल वस्तु के रूप में माना जाएगा ",

(18) उपरोक्त प्रावधानों में से एक अवलोकन से पता चलता है कि एक राज्य कानून की व्याख्या करते समय जो घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाता है, खंड (सीए) में निहित प्रतिबंध को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रतिबंध क्या है? जब धान की बिक्री या खरीद पर एक कर राज्य कानून के तहत लेविबल होता है और चावल "ऐसे धान से खरीदे गए चावल को भारत से बाहर कर दिया जाता है, धान और चावल को एक एकल वस्तु के रूप में माना जाएगा" तो उप-धारा के प्रयोजनों के लिए (3) धारा 5 "। संसद ने एक सीमित

कल्पना पेश की है। यह केवल धारा 5 के खंड (3) द्वारा कवर किए गए लेनदेन के संबंध में है कि चावल और धान को एकल वस्तु के रूप में माना जाता है (१९) श्री सरीन यह बताने के लिए दर्द में थे कि खंड १५ के संशोधन का प्राथमिक कारण खंड (सीए) शुरू करके "कर से छूट का लाभ" और चावल के अप्रत्यक्ष कर से बचने के लिए था। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना था। इस प्रकार, वकील ने कहा कि उत्तरदाताओं को धान और चावल को दो अलग-अलग वस्तुओं के रूप में इलाज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्या ऐसा है ?

(२०) धारा १४ (i) (i और ii) का एक विद्रोह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि धान और चावल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। क्लॉज (सीए) को पेश करके, धारा 5 के उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए "भेद को काल्पनिक रूप से तिरछा कर दिया गया है। इस प्रावधान ने पूरी तरह से भेद को नष्ट नहीं किया है। यह केवल 1956 अधिनियम की धारा 5 (3) द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में है कि एक कल्पना को पेश किया गया है। अंतर-राज्य व्यापार के मामले में केंद्रीय बिक्री कर की लेवी के उद्देश्य से, धान और चावल अभी भी दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। हालांकि, ऐसे मामले में जहां धान से निकले चावल को भारत से बाहर कर दिया जाता है, दोनों को धारा 5 (3) के सीमित उद्देश्य के लिए एक ही वस्तु के रूप में माना जाता है।

(२१) धारा ५ क्या है? यह अंडर के रूप में पढ़ता है-

5. "आयात या निर्यात के दौरान होने वाले सामानों की बिक्री या खरीद कब होती है- (1) माल की बिक्री या खरीद को माल के निर्यात के दौरान होने के लिए समझा जाएगा। भारत का क्षेत्र तभी तभी होता है जब बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात होते हैं या माल के लिए शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होते हैं, जब माल भारत के सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर जाता है।

(२) माल की बिक्री या खरीद को भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान केवल तभी होने के लिए माना जाएगा जब बिक्री या खरीद या तो इस तरह के आयात के लिए या शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित हो माल से पहले माल भारत के सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर गया है।

(3) उप-धारा (1) में निहित कुछ भी नहीं, किसी भी सामान की भारत के क्षेत्र से बाहर उन सामानों के निर्यात को बिक्री या खरीदारी से पहले अंतिम बिक्री या खरीद, को भी इस तरह के निर्यात के दौरान माना जाएगा, अगर इस तरह की अंतिम बिक्री या खरीद के बाद हुई, और इसके अनुपालन के

उद्देश्य से, समझौते या इस तरह के निर्यात के संबंध में या उसके लिए आदेश।
"

(२२) क्लॉज़ (१) और (३) माल के निर्यात से निपटते हैं। क्लॉज़ (२) माल के आयात से संबंधित है। वर्तमान मामले में, हम केवल निर्यात से चिंतित हैं। इस प्रकार, खंड (२) प्रासंगिक नहीं है। क्लॉज़ (१) उन वस्तुओं की खरीद को कवर करता है जो निर्यात को अवसर देते हैं। दूसरे शब्दों में, निर्यातक द्वारा बिक्री या विदेशी खरीदार द्वारा खरीद को कवर किया गया है। क्लॉज़ (३) निर्यात से पहले बिक्री या खरीद से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, निर्यातक द्वारा खरीद को काल्पनिक रूप से निर्यात के दौरान माना जाता है।

(२३) वर्तमान मामले में क्या स्थिति है? याचिकाकर्ता एक मिलर है। यह मिलिंग के लिए आयोग एजेंट से धान खरीदता है। इसे संसाधित करने के बाद, याचिकाकर्ता निर्यातक को चावल बेचता है। फिर निर्यातक विदेशी खरीदार को चावल बेचता है। क्लॉज़ (१) विदेशी खरीदार को निर्यातक द्वारा बिक्री को छूट देता है। क्लॉज़ (३) जिसे वर्ष 1976 में पेश किया गया था, वह उस पेन्टिमेंट सेल को छूट देता है जो निर्यात के अवसर पर है। मिलर द्वारा चावल की बिक्री निर्यातक को या मिलर से निर्यातक द्वारा खरीद। हालांकि, याचिकाकर्ता को आयोग एजेंट द्वारा धान की बिक्री धारा 5 के किसी भी प्रावधान द्वारा कवर नहीं की गई है।

(२४) श्री सरिन ने कहा कि इस तरह की व्याख्या धारा १५ में खंड (सीए) को शुरू करने में संसद की वस्तु को पूरी तरह से हरा देगी। क्या ऐसा है?

(25) 17 अगस्त 1995 को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यूनाइटेड राइस लैंड लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (सुप्रा) के मामले का फैसला किया। यह आयोजित किया गया था कि धान और चावल को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के तहत माल घोषित किया गया है। ये दो अलग-अलग वस्तुएं हैं जो धारा 6 के तहत कर के अधीन हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं - यूनाइटेड रिकलैंड लिमिटेड और

अन्य लोग "भारत के बाहर चावल के निर्यातक" थे। उन्होंने "पंजाब और हरियाणा के राज्यों से धान खरीदा भारत के बाहर चावल के निर्यात के लिए इसे डीहॉकिंग के प्रयोजनों के लिए।" इस प्रकार, उन्हें धान पर खरीद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि धान और चावल के दो अलग - अलग वस्तुओं के कारण, यहां तक कि चावल का निर्यातक धान की खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। दूसरे शब्दों

में, इसे केंद्रीय अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत कोई लाभ नहीं मिला। इस कठिनाई को कम करने के लिए, संसद ने क्लॉज (सीए) की शुरुआत की और बशर्ते कि क्लॉज (3) द्वारा कवर किए गए लेनदेन के लिए, धान और चावल को एकल वस्तु के रूप में माना जाएगा। और अधिक कुछ नहीं। नतीजतन, एक मिलर जो धान खरीदता है और विदेशी खरीदार को चावल बेचता है, को खरीद कर के भुगतान से छूट दी जाती है। हालांकि, मामले में, मिलर केवल एक मध्यस्थ को बेचता है। निर्यातक, मिलर द्वारा धान की खरीद का लेनदेन क्लॉज (3) के तहत कवर नहीं किया गया है।

(२६) श्री सरीन ने हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की धारा १२ के प्रावधानों का उल्लेख किया। यह अंतर बताता है कि "माल की बिक्री या खरीद पर एक कर इस अधिनियम के तहत लागू नहीं किया जाएगा .. जहां इस तरह की बिक्री या खरीद माल के आयात के दौरान या माल के निर्यात के दौरान होती है। भारत का क्षेत्र। " इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां माल के निर्यात के दौरान बिक्री या खरीद होती है, कर को राज्य अधिनियम के तहत लेबल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह सवाल कि निर्यात या खरीद को निर्यात के दौरान होने के लिए कब कहा जा सकता है, केंद्रीय अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में तय किया जाना है। इस प्रकार, जब धारा 12 और 5 को एक साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि निर्यातक द्वारा खरीद और बिक्री पर राज्य अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं है। यह क़ानून निर्यात के पाठ्यक्रम में बिक्री या खरीद के हिस्से के रूप में आयोग एजेंट से मिलर द्वारा धान की खरीद का संबंध नहीं रखता है।

(27) श्री सरीन ने धारा 27(एल)(ए)(iv) के प्रावधानों का हवाला यह तर्क देना के लिए किया कि धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लेनदेन को डीलर के कर योग्य टर्नओवर से बाहर रखा गया है। यह निस्संदेह ऐसा है। हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान मामले में शामिल लेनदेन धारा 12 द्वारा कवर नहीं किया गया है।

(28) श्री सरीन ने कहा कि धान और चावल के सामान हैं विशेष महत्व। एक विशेष प्रावधान जो भेद को नष्ट कर देता है बनाया गया है, कल्पना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। उन्होंने ईस्ट एंड डेवेलिंग्स कंपनी बनाम फिन्सबरी बरो परिषद, (2) आंध्र प्रदेश राज्य बनाम वल्लभपुरम रावी (3) द आयकर आयुक्त पटियाला बनाम श्री सरूप कृष्ण (4) और एम गैनन डंकर्ले एंड कंपनी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में और अन्य (5). निर्णयों को संदर्भित किया ।

6501.L.R. पंजाब और हरियाणा 2002 (1)

(२९) हरियाणा अधिनियम की धारा १, के तहत, घोषित माल पर कर को अनुसूची 'डी' में बताए गए चरण में लेबल किया गया है। शेड्यूल के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि जब कमोडिटी को राज्य में आयात किया जाता है, तो कर योग्य घटना, "इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए एक डीलर द्वारा राज्य के भीतर पहली बिक्री" के चरण में है। जब माल राज्य के भीतर खरीदा जाता है, तो लेवी का चरण "कर का भुगतान करने के लिए एक डीलर द्वारा राज्य के भीतर अंतिम खरीद है।" यह प्रावधान प्रासंगिक होता अगर धारा 15 (सीए) द्वारा पेश किया गया कथा धारा 5 के खंड (3) द्वारा कवर किए गए लेनदेन तक सीमित नहीं था। संसद ने स्वयं कल्पना के दायरे को सीमित कर दिया था, अदालत एक लेनदेन के लिए लाभ का विस्तार नहीं कर सकती है जो प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया गया है। यह प्रावधान की सादी भाषा के लिए हिंसा करेगा।

(३०) यह निस्संदेह सच है कि ईस्ट एंड डेवलिंग (सुप्रा) के मामले में, उनके लॉर्डशिप के रूप में निरीक्षण करने के लिए प्रसन्न थे-

"यदि आप एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए प्रतिबंधित हैं, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, तब तक वास्तविक परिणामों और घटनाओं के रूप में भी कल्पना करें, जो कि यदि मामलों की पुटीय स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से प्रवाहित हो जाना चाहिए। इसके साथ या इसके साथ कानून कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, आपको उस राज्य के अपरिहार्य कोरोलरीज मामलों के लिए अपनी कल्पना को चकित करने या अनुमति देना होगा। "

(३१) इस सिद्धांत को शीर्ष न्यायालय के साथ -साथ इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में मान्यता दी गई है। हालांकि, इन मामलों में याचिकाकर्ता इस फैसले से इस तथ्य को देखते हुए कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं कि संसद ने एक सीमित उद्देश्य के लिए कल्पना को पेश किया है।

यह पार्लिमेंट द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर है कि सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। उससे परे नहीं।

(३२) श्री सूर्य कांट ने वीरुमल के मामले (सुप्रा) में निर्णय का उल्लेख किया था। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील यह बताने के लिए दर्द में था कि निर्णय कानून के सही विवरण को नहीं बदलता है। हमारे उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, हम श्री सरीन द्वारा उठाए गए इस विवाद में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

(३३) एडवोकेट जनरल को निष्पक्षता में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने विभिन्न अदालतों के फैसलों को संदर्भित किया था। समेकित

काँफी लिमिटेड बनाम काँफी बोर्ड, बैंगलोर, (6) निक्का ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (7) बिस्मिल्लाह एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (8) मोहम्मद ईशक और संस बनाम बनाम कर्नाटक, बैंगलोर में वाणिज्यिक करों के आयुक्त, (9) और संप्रभु मसालों बनाम केरल राज्य, (10)। हालांकि, हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर, हम प्रत्येक मामले को अलग से नोटिस करना आवश्यक नहीं मानते हैं।

(३४) श्री सरीन ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि विधायिका का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना था। इस प्रकार, इसने एक कल्पना को पेश किया था ताकि हमारी कीमतें अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धी थीं। नतीजतन, हमें प्रावधान के लिए एक प्रतिबंधित अर्थ नहीं देना चाहिए।

(३५) यह निस्संदेह सच है कि राष्ट्र को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह निर्यात को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाता है। हालांकि, यह याद रखना समान रूप से प्रासंगिक है कि राज्य के राजस्व भी महत्वपूर्ण हैं। कोई भी राज्य के हितों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकता है। एक संतुलन पर हमला करने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, संसद ने एक सीमित कल्पना पेश की है। इसने एक सीमित उद्देश्य के लिए चावल और धान को एक वस्तु के रूप में माना है। इस संशोधन से, इसने उन मिलर्स को सक्षम किया है जो धान की खरीद पर कर के भुगतान से बचने के लिए प्रत्यक्ष निर्यातक हैं। हालांकि, यह लाभ उन मिलर्स को उपलब्ध नहीं कराया गया है जो एक निर्यातक को बेचते हैं और सीधे निर्यात नहीं करते हैं। संसद लोगों के हितों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। यह अनुभव द्वारा की गई आवश्यकताओं के आधार पर क़ानून लागू करता है। सीमित कल्पना को पेश करने वाला प्रावधान संवैधानिक मापदंडों के भीतर है। यह एक उचित संतुलन पर हमला करता है। हम इस कल्पना को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं कि क़ानून के व्यक्त शब्द क्या प्रदान करते हैं।

(३६) उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहला प्रश्न उत्तर दिया गया है। यह माना जाता है कि निर्यातक द्वारा बिक्री और खरीद को छूट दी जाती है। निर्यातक द्वारा बिक्री को खंड (1) में प्रावधान के आधार पर छूट दी गई है और खरीद को खंड 5 के खंड (3) के तहत कवर किया गया है। माल के निर्यात का कोर्स। इस प्रकार, यह क़ानून के तहत कर की लेवी से छूट के प्रावधान द्वारा कवर नहीं किया गया है।

(३7) श्री सरीन ने कहा कि संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं। पारदीप पोर्ट ट्रस्ट बनाम बिक्री कर अधिकारी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के फैसले के मद्देनजर, (11) अपील का उपाय आदि रिट याचिका की रखरखाव

के लिए कोई बार नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अनंतिम मूल्यांकन के आदेश, जिनमें से प्रतियां रिकॉर्ड पर उत्पादित की गई हैं, अनुचित हैं। दूसरी ओर श्री सूर्य कांत ने कहा कि अधिनियम की धारा 28-बी के तहत लगाए गए आदेशों को पारित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के पास अधिनियम की धारा 39 और 41 के तहत एक वैधानिक उपाय है। किसी भी घटना में, अधिवक्ता जनरल ने श्री एस.के. के निर्देशों पर कहा। यादव, संयुक्त निदेशक (कानूनी), कि मामले में, याचिकाकर्ता उस समय के भीतर एक अपील दायर करते हैं जो अदालत द्वारा दी जा सकती है, राज्य सीमा के बारे में आपत्ति नहीं उठाएगा।

(38) यह निस्संदेह सच है कि एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका की रखरखाव के लिए एक पूर्ण बार नहीं है। यह भी सही है कि जब किसी क़ानून के वायरस शामिल होते हैं या संवैधानिक महत्व का एक मुद्दा होता है, तो नागरिक सामान्य रूप से अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार हो सकता है। हालांकि, तथ्यों और लेनदेन में एक जांच से जुड़े मामलों में। रिट कोर्ट में एक स्पष्ट बाधा है। आम तौर पर, यह सबूतों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है और तथ्य के सवालों पर निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। इन्हें हमेशा क़ानून के तहत अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाना है।

यह केवल तब होता है जब एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त होता है या एक वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में होता है जो अदालत सर्टिफिकेट के एक रिट के मुद्दे से हस्तक्षेप करती है।

(39) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक द्वारा दायर किए गए रिटर्न की शुद्धता या अन्यथा निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए अलग-अलग वर्षों के लिए रिकॉर्ड के मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में निपटा नहीं जा सकता है। किसी भी घटना में, विशुद्ध रूप से कानूनी मुद्दे का फैसला किया गया है, इस मामले की अब क़ानून के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए। इस स्थिति में, हम निर्देशित करते हैं कि मामले में, याचिकाकर्ताओं के पास अनंतिम मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ कोई शिकायत है, वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति की पुनरावृत्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने के हकदार होंगे। मामले में, इस तरह की अपील दायर की जाती है, इस पर विचार किया जाएगा और योग्यता के तहत

उचित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसे सीमा के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(४०) इस प्रकार, यहां तक कि दूसरा प्रश्न का उत्तर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दिया गया है।

(41) श्री झिंगन, याचिकाकर्ता के वकील, सीडब्ल्यूपी संख्या 5856 में 2001 में एक अतिरिक्त आधार तैयार किया गया।

उन्होंने आग्रह किया कि 29 नवंबर, 2000 को दिनांकित पत्र, याचिका के साथ एनेक्सोर पी। 2, राज्य सरकार ने अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें आकलन के लिए मामलों पर विचार करना होगा और बिक्री कर के प्रकाश में लेवी पर विचार करना होगा। वीरुमल के मामले (सुप्रा) में निर्णय। उन्होंने कहा कि अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों को निर्देश देने में प्राधिकरण की कार्रवाई अवैध और अस्थिर है।

(४२) यह निस्संदेह सही है कि एक वैधानिक प्राधिकरण में कानून द्वारा निहित विवेक को प्रशासनिक निर्देशों के मुद्दे से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, अधिकारियों का ध्यान केवल क्षेत्राधिकार न्यायालय के निर्णय के लिए आमंत्रित किया गया है। इस न्यायालय की एक बेंच द्वारा लिया गया दृश्य राज्य के भीतर हर ट्रिब्यूनल कामकाज के लिए बाध्यकारी है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल अधिकारियों के नोटिस के लिए निर्णय लाने से, राज्य सरकार ने अपने विवेक को नियंत्रित, नियंत्रित या सीमित कर दिया है।

(४३) कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया था।

(४४) उपरोक्त के मद्देनजर, हम इसे धारण करते हैं:-

(i) इन मामलों में याचिकाकर्ताओं द्वारा धान की खरीद कर की लेवी से छूट नहीं है। मामला नहीं है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 5 और राज्य अधिनियम के 12 के मापदंडों के भीतर गिरावट।

(ii) याचिकाकर्ताओं के पास हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, जहां तक मूल्यांकन आदि के आदेशों के लिए चुनौती का संबंध है। उन्हें कानून के तहत उपाय के लिए फिर से आरोपित किया गया है।

(iii) प्राधिकरण वीड लेटर द्वारा जारी किए गए निर्देश, दिनांक २ ९ नवंबर, २०००, कानून की कोई दुर्बलता से पीड़ित हैं ताकि इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कॉल किया जा सके।

(४५) रिट याचिकाओं को तदनुसार इस शर्त के अधीन कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का हकदार होंगे। इन मामलों की परिस्थितियों में, हम लागत के अनुसार कोई आदेश नहीं देते हैं।

आर.एन.आर.

एस.एस. निज्जर से पहले, जे
एच.एम.टी. लिमिटेड-याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य-उत्तरदाता

सी -डब्ल्यू.पी. नहीं। 2000 का 6809

8 नवंबर, 2001

भारत का संविधान, 1950-कला। 226-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-SS। 2 (ए) और 10 (1) क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार-औद्योगिक विवाद-रेफरेंस-रेफरेंस-डिस्मिज़ल से सेवा-कार्यकाल से अंतिम बार मुंबई ऑर्डर ऑफ़ डिसमिसल में कार्यरत थे, हालांकि बंगलौर में मुख्य कार्यालय द्वारा पारित किया गया था, लेकिन चंडीगढ़-चंदिगढ़ प्रशासन में विवाद का संदर्भ दिया। धारा 10 (1) (सी) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार-उच्च न्यायालय को चुनौती

- (1) (1997) 104 एसटीसी 362
- (2) (2) १९५१ (२) ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट 587
- (3) (३) १९४ (४) एससीसी ४१०
- (4) (४) १९ (५) (२) पीएलआर १०९
- (5) (५) १९९३ (१) एससीसी ३६४
- (6) (6) (1980) 46 एसटीसी 164
- (7) (7) (१९९६) १०० एसटीसी १४२
- (8) (8) (1989) 73 एसटीसी 135
- (9) (9) (1992) 87 एसटीसी 36
- (10) (१०) (१९९०) ११० एसटीसी ४२९
- (11) **(11) JT 1998 (4) SC 483**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ

सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

पारिंदर सिंह

जींद, हरियाणा